1. मॉड्यूल और इसकी संरचना

मॉड्यूल विस्तार	
विषय का नाम	अर्थशास्त्र
पाठ्यक्रम का नाम	अर्थशास्त्र 01 (कक्षा- 11 सेमेस्टर-1)
मॉड्यूल का नाम / शीर्षक	भारत और इसके पडोसियों के तुलनात्मक विकास अनुभव- भाग 1
मॉड्यूल आईडी	keec_11001
पूर्व-अपेक्षित	जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, आयोजना की मूल अवधारणाओं की जानकारी
उद्देश्य	**इस अध्याय को पढ़ने के बाद छात्र :** 1. भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास के पथ को समझ सकेंगे. 2. इन देशों में विकास कार्यनीतियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ सकेंगे. 3. भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास संकेतकों का विश्लेषण और तुलना कर सकेंगे. 4. इन देशों में मानव विकास के स्तर के प्रति जागरूकता बढ़ा सकेंगे. 5. इन तीन देशों में विकास कार्यनीतियों का तुलनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे.
मुख्य शब्द	आर्थिक सुधार, आर्थिक आयोजना, आयात प्रतिस्थापन , निर्यात संवर्धन , मानव विकास सूचकांक, स्वतंत्रता संकेतक

2. विकास दल

भूमिका	नाम	सम्बद्धता
राष्ट्रीय MOOC समन्वयक (NMC)	प्रो. अमरेंद्र पी बेहरा	सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
कार्यक्रम के समन्वयक	डॉ. मो. मामूर अली	सीआईईटी, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
पाठ्यक्रम समन्वयक (सीसी) / पीआई	प्रो नीरजा रश्मि	डीईएसएस, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
विषय वस्तु विशेषज्ञ	डॉ. अन्नपूर्णा माधुरी	केन्द्र संचालक,एसएमआईओ आरई एकेदमी फॉर टीचर ट्रेनिंग, संदूर, कर्नाटक
समीक्षा दल	डॉ. जन्मेजय खुंटियां डॉ. रजनी सिंह	स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
अनुवाद	डॉ. हरियश राय	पूर्व डीजीएम (ओएल & कॉर्पोरेट संचार), बैंक ऑफ बड़ौदा

विषय तालिका :

1. भूमिका
2. ऐतिहासिक पदचिन्ह : एक संक्षिप्त विवरण
3. विकास संकेतक
4. विकासात्मक कार्यनीतियां – एक तुलनात्मक विश्लेषण
5. सारांश

1. भूमिका

पिछले कुछ दशकों में विश्व के अधिकांश देशों में, वैश्वीकरण व्यापक आर्थिक रूपांतरण लेकर आया है. इसने देशों को वैश्विक प्रतियोगिता की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी - अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बाध्य किया. इसके परिणामस्वरूप, पिछले तीन दशकों में घरेलू बाजारों को वैश्विक प्रतियोगिता के लिए खोलने की प्रक्रिया तेज हो गई है . अनेक देश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सार्क, यूरोपीय संघ, आसियन, जी- 8 और ऐसे अन्य कई क्षेत्रीय और वैश्विक समूह बना रहे हैं. इन दशकों के दौरान भारत, चीन और पाकिस्तान में विभिन्न सरकारों द्वारा, इन देशों को विश्व भर में हो रहे विकास के समकक्ष लाने के लिए सघन प्रयास किए गए.

ये देश भौगोलिक सीमाओं से विभाजित हैं, हालांकि इनमें सांस्कृतिक समानताएं हैं. भारत, पाकिस्तान और चीन ने आर्थिक विकास की राह पर अपनी यात्रा लगभग एक समय पर ही प्रारम्भ की. जहां भारत और पाकिस्तान 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होते हुए अलग देशों के रुप में उभरे, वहीं 1949 में चीन चीनी जनवादी गणतंत्र के रुप में स्थापित हुआ. यह मॉडयूल भारत के विकास और उसके अनुभवों का उसके नजदीकी पडोसियों, चीन और पाकिस्तान के साथ तुलनात्मक अध्ययन करता है.

2. ऐतिहासिक पदचिन्ह : एक संक्षिप्त वर्णन

चीन

1949 में चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना से, व्यक्तियों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, उद्यमों और भूमि को सरकारी नियंत्रण में लाया गया. प्रारम्भिक वर्षों (**1949** से **1957** तक) में एक घरेलू नीति अपनाई गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना , भूमि सुधारों को लागू करना, किसानों को शिक्षित करना, बुद्धिजीवियों और व्यापारियों की सहभागिता से उत्पादन बहाल करना और अलगाव को रोकना था. चीनी जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच संबंध द्वेषपूर्ण राजनैतिक वातावरण के कारण सीमित ही रहे. चीन ने अपने लोगों पर पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया और अपनी संस्कृति को पुन: बहाल किया. चीन ने यू.एस.एस.आर के साथ मित्रता और सहयोग की एक संधि की. लेकिन यू.एस.एस.आर से आर्थिक सहायता के एवज में, जापान के विरुद्ध प्रतिरोध ,डालियन पर सोवियत कब्जा और सोवियत मंगोलिया की मान्यता को स्वीकार करना चीन के लिए कठिन था. कोरिया युद्ध के परिणामस्वरूप चीन में आमूल सुधारों में तेजी आई.

1953 में चीन में सभी उद्योगों और बड़े वाणिज्यिक उद्यमों का राष्ट्रीयकरण करने, संसाधनों के निजी स्वामित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाएँ अपनाई गईं. आगे की ओर बड़ा कदम के रुप में (जीएलएफ) अभियान की शुरुआत की गई. समुदाय पद्धति के अंतर्गत भूमि का सामूहिकीकरण किया गया, जहां सब लोग सामूहिक रुप से ज़मीनों पर खेती करते थे. देश का व्यापक स्तर पर औद्योगीकरण करने के उद्देश्य से लोगों को अपने घर के आँगन में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया. जीएलएफ

अभियान के समक्ष कई समस्याएँ आई. भयानक सूखा पड़ा था. रूस ने अपने उन व्यावसायिकों को वापस बुला लिया, जो औद्योगीकरण प्रक्रिया में सहायता करने के लिए भेजे गये थे , 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति (1966-76) की शुरुआत की जिसके अंतर्गत छात्रों और व्यावसायिकों को गाँवों में काम करने और सीखने के लिए भेजा गया. चीन के वर्तमान तीव्र औद्योगिक विकास के सूत्र 1978 में प्रारम्भ किए गए सुधारों में पाये जा सकते हैं.

1978 में आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिससे बाह्य विश्व के लिए व्यापार खुला, आन्तरिक निवेशों में बढ़ोतरी और निर्यात में वृद्धि हुई. कृषि क्षेत्र में, सामूहिक भूमि को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया जो वैयक्तिक परिवारों को केवल उनके अपने उपयोग के लिए (स्वामित्व के लिए नहीं) आवंटित किए गए. राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को भी प्रतियोगिता में उतारा गया. विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों को मंजूरी देने के अतिरिक्त,शहरी व ग्रामीण उद्यमों के साथ, निजी क्षेत्र के उद्यमों को प्रोत्साहित किया गया. 1990 में, विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए.

चीनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर छाप छोड़ने वाली एक अन्य विशेषता
'एक संतान नियम' लागू करना है. यह चीन में लगातार बढ़ती आबादी को रोकने के लिए आवश्यक हो गया था.

1990 के दशक के पूर्वार्ध में शहर आधारित विकास मॉडल पर ध्यान केन्द्रित किया गया और 21 वीं शताब्दी के पहले दशक में सस्ती वस्तुओं के स्थान पर महंगी तकनीकी वस्तुओं के निर्यात की तरफ झुकाव हुआ. चीन वर्ष 2000 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में शामिल हुआ और तत्पश्चात, चीन के निर्यात का 95 प्रतिशत निर्मित वस्तुएं थीं, जो जापान से ज्यादा था. 2014 तक बाह्य निवेश आंतरिक निवेशों से अधिक हो गये, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई.

पाकिस्तान

पाकिस्तान 1947 में एक स्वतंत्र देश के रुप में उभरा और भारत के
समान आर्थिक नीतियों को अपनाया. पाकिस्तान ने, 1950 और 1960 के दशकों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था और आयात प्रतिस्थापन पर आधारित औद्योगीकरण के लिए एक नियंत्रित नीतिगत स्वरूप को अपनाया. इस नीति में उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में शुल्क दर संरक्षा को प्रतियोगी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण के साथ जोड़ा गया. हरित क्रांति की शुरुआत से मशीनीकरण हुआ और कुछ क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हुई. जिसने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया. इसने कृषि क्षेत्र को व्यापक रुप से बदल दिया. 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसे 1970 के उत्तरार्ध में और 1980 के दशक में पलट दिया गया, जब अराष्ट्रीयकरण और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन , मुख्य ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र थे. पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों से वित्तीय सहायता और मध्य- पूर्व के आप्रवासियों से भी धन प्राप्त किया. इससे देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायता मिली. सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन भी दिए . 1988 में देश में सुधारों की शुरुआत की गई.

भारत

1947 में स्वतंत्रता के समय, शून्य से शुरुआत करना, विभाजन के समय अपनी अधिकांश उत्पादक भूमि को गंवा देना, भारत के सामने ऐसी अनेक चुनौतियां थीं जिनका सामना करना था. मिश्रित अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजना के अंगीकरण ने पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की. कृषि क्षेत्र की नीतियों ने भूमि सुधारों, आत्म निर्भरता की नीतियों और हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा

आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करने से औद्योगिक क्षेत्र को बल मिला. **1991** में वैश्वीकरण- निजीकरण -उदारीकरण की नीतियों द्वारा लाए गए सुधारों ने विकास की गति विशेष, विकास समानता के साथ विकास, और रोजगार सर्जन की गति को तेज कर दिया. आर्थिक सुधारों के बाद भारत में व्यापक परिवर्तन हुए,भारत में विश्व की एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रुप में उभरने के मार्ग पर स्वयं को स्थापित किया. इससे जीडीपी में सेवा क्षेत्र के योगदान में तेजी से वृद्धि हुई. देश के जीडीपी में निर्माण क्षेत्र के योगदान में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई. सेवा क्षेत्र की लगातार वृद्धि ने अर्थव्यवस्था को बाह्य आर्थिक झटकों के प्रति लचीला बना दिया. बढ़ते हुए मध्यवर्ग और इसकी बढ़ती व्यय योग्य आय द्वारा निवेश के अवसर पैदा किए जाते है. भारत भी व्यवसायों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है, आधारभूत संरचना में विदेशी निवेश की व्यापक संभावनाएं खोली हैं. वैश्विक निवेशकों के लिए बिजली, बंदरगाहों, और सड़कों के क्षेत्र में कई उद्यम है. सुधारों के बाद भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे **2011** तक भारत बड़े निर्यातकों में से एक बन गया. तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, भारत अभी भी गरीबी, गुणवत्तापरक शिक्षा का अभाव, असमानता और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक – आर्थिक चुनौतियों की जकड़ में है.

3. विकास संकेतक

भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास के पथ की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ, आइये हम इन देशों के विकास के कुछ संकेतकों के की तुलना करें :

तालिका: 1
जनसांख्यिकी संबंधी संकेतक

संकेतक	देश		
	भारत	चीन	पाकिस्तान
अनुमानित आबादी (दस लाख में) (2015)	1311	1371	188
आबादी की वार्षिक वृद्धि (2015)	1.2	0.5	2.1
सघनता (प्रति वर्ग किमी.)	441	146	245
लिंग अनुपात (2015)	929	941	947
प्रजनन दर (2014)	2.4	1.6	3.6
शहरीकरण (2015)	33	56	39

स्त्रोत *:* भारतीय आर्थिक विकास,एनसीईआरटी *, 2017*

जैसा कि तालिका **1** में दिखाया गया है, चीन की तुलना में पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि की दर उच्चतम और भारत में काफी उच्च बनी हुई है. चीन में इस बदलाव का एक प्रमुख कारण तीन दशकों से अपनाया गया ‘ एक संतान नियम ’ हो सकता है. पाकिस्तान में प्रजनन दर बहुत ज्यादा है, इसके बाद भारत और चीन आते हैं. भारत और पाकिस्तान की तुलना में जनसंख्या की कम सघनता चीन के लिए सदैव लाभप्रद रही है. शहरीकरण में चीन और पाकिस्तान बेहतर संकेत दर्शाते हैं. भारत, केवल **33** प्रतिशत पर सबसे कम

शहरीकृत है और इसका आशय यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही कृषि के बाहर रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल रहे हैं. अनुमान के अनुसार, भारत में लिंग अनुपात **1000** पुरुषों की तुलना में **929** महिलाओं का है, इसके बाद चीन (**941**) और पाकिस्तान **(947)** है. ये आंकड़े तीनों समाजों का सामाजिक पिछड़ापन दर्शाते हैं, इसके जिसके प्रमुख कारण लड़कों की चाह और कन्या भ्रूण हत्या हैं.

तालिका : 2

जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर (%)

देश	**वर्ष**	
	1980-90	**2011-15**
भारत	**5.7**	**6.7**
चीन	**10.3**	**7.9**
पाकिस्तान	**6.3**	**4.0**

स्त्रोत *:* भारतीय आर्थिक विकास,एनसीईआरटी , *2017*

तालिका 2 के अनुसार, 1980-90 से 2011-15 के दौरान भारत की वृद्धि दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है जबकि चीन और पाकिस्तान गिरावट दर्शाते हैं. यह भी देखा जा सकता है कि 1980-90 के दौरान, चीन की वृद्धि दर भारत और पाकिस्तान से अधिक दो अंकों में थी जो 2011- 15 के दौरान काफी गिरावट दर्शाती है .

तालिका : 3

2014-15 में व्यावसायिक संरचना (%)

	देश		
क्षेत्र	**भारत**	**चीन**	**पाकिस्तान**
कृषि	50	28	43
उद्योग	21	29	23
सेवाएं	29	43	34
कुल	**100**	**100**	**100**

स्त्रोत *:* भारतीय आर्थिक विकास,एनसीईआरटी , *2017*

तालिका 3 दर्शाती है कि चीन में कृषि पर निर्भरता सबसे कम है. इसके बाद पाकिस्तान है जबकि 50 प्रतिशत भारतीय आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है. चीन में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान की तुलना में बहुत बड़े हैं जो उसके अधिक विकास में सहायक है.

तालिका : 4

जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान (%)

क्षेत्र	**देश**		
	भारत	**चीन**	**पाकिस्तान**
कृषि	17	9	25
उद्योग	30	43	21
सेवाएं	53	48	54
कुल	**100**	**100**	**100**

स्त्रोत *:* भारतीय आर्थिक विकास,एनसीईआरटी *, 2017*

जबकि तीनों देशों में जीडीपी में कृषि का योगदान सबसे कम है, भारत और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान करता है जो यह दर्शाता है कि उभरता हुआ सेवा क्षेत्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.(तालिका - 4) सामान्यत: आर्थिक विकास प्रक्रिया में सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र का विकास और उसके बाद निर्माण क्षेत्र की वृद्धि ओर बाद में सेवा क्षेत्र का विकास शामिल होता है. चीन ने विकास का सामान्य मार्ग का अनुसरण किया जबकि भारत और पाकिस्तान ने वहीं स्वरूप नहीं दिखाया .

तालिका: 5

विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि की प्रवृतियां 1980-2013

देश	1980-90			2011-15		
	कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा
भारत	3.1	7.4	6.9	2.3	5	8.4
चीन	5.9	10.8	13.5	4.1	8.1	8.4
पाकिस्तान	4	7.7	6.8	2.7	3.4	4.4

स्त्रोत *:* भारतीय आर्थिक विकास,एनसीईआरटी *, 2017*

जैसा कि तालिका 5 में हम देखते हैं, कि पिछले तीन दशकों के दौरान सबसे अधिक कार्यदल को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र की वृद्धि में काफी गिरावट आई. चीन अपने सेवा व औद्योगिक क्षेत्रों में द्विअंकीय वृद्धि दर को बनाए रखने में असफल रहा. भारत अपने सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में बढ़ोतरी दर्शाता है, हालांकि निर्माण क्षेत्र गिरावट दर्शाता है. पाकिस्तान तीनों क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट दर्शाता है.

तालिका : 6
मानव विकास के कुछ चयनित संकेतक, 2015

मद	भारत	चीन	पाकिस्तान
मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)	0.609	0.727	0.538
पदक्रम (एचडीआई पर आधारित)	130	90	147
जन्म के समय अनुमानित जीवन काल (वर्ष)	68.2	75.8	66.2
प्रौढ़ साक्षरता दर (15 वर्ष और उससे अधिक %)	72.2	96.4	56.4
प्रति व्यकित जीडीपी (पीपीपी यूएस $)	5730	13,572	4706
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का % (2011 के लिए 3.10 $ प्रतिदिन पर)	58	32	44
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म के अनुसार)	38	9	66
मातृ मृत्यु दर (प्रति एक लाख जन्मों के अनुसार)	174	27	178
उन्नत स्वच्छ सुविधाओं का उपयोग करने वाली आबादी (%)	40	77	64
उन्नत जल सुविधाओं तक स्थायी पहुंच वाली आबादी का %	94	96	91
कम पोषित बच्चों का प्रतिशत	15	9	22

स्त्रोत *:* भारतीय आर्थिक विकास,एनसीईआरटी *, 2017*

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के संदर्भ में भारत के **0.61** और पाकिस्तान के **0.54** की तुलना में, चीन **0.73** के साथ काफी बेहतर स्थिति में है . उच्च एचडीआई का **90** वां स्थान, निर्यातोन्मुख निर्माण क्षेत्र के साथ – साथ उसकी आबादी की वृद्धि को नियंत्रित करने की नीतियों के कारण हो सकता है जो उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी को बढ़ाते हैं, उच्च एचडीआई स्थान, लोगों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता सुविधाओं में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और लोगों को बेहतर पोषण के संबंध में , देश का बेहतर निष्पादन दर्शाता है. पाकिस्तान में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है और चीन में सबसे कम है, जो इन देशों में चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं की उपलब्धता के स्तर को दर्शाता है. चीन में प्रति एक लाख जन्मों में मातृ मृत्यु दर भारत के **174** और पाकिस्तान के **178** की तुलना में **27** है. बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के संदर्भ में, चीन ने **2012** में **65** प्रतिशत से **2016** में **77** प्रतिशत तक सुधार दर्ज किया जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. जबकि **2012** में पाकिस्तान की **47** प्रतिशत आबादी की बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच थी, यह **2016** में बढ़कर **64** प्रतिशत हो गई. भारत **2012** में केवल **36** प्रतिशत आबादी की स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच के कारण निराशाजनक स्थिति में था. यह **2016** में बढ़कर **40** प्रतिशत हो गया. इस संबंध में स्वच्छ भारत अभियान भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. चीन गरीबी रेखा के नीचे आबादी की प्रतिशतता कम करने में भारत और पाकिस्तान से आगे है जिसका अर्थ उच्चतर जीडीपी, उच्चतर प्रति व्यक्ति आय और बेहतर मानव विकास संकेतक हैं

वे संकेतक जो किसी देश में सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रता के स्तर को दर्शाते हैं, स्वतंत्रता संकेतक कहलाते है. स्वतंत्रता संकेतक मानव अधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के प्रति शून्य सहनशीलता के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान दर्शाते हैं. इन मूल्यों के प्रति सम्मान श्रेष्ठ प्रशासन और व्यक्ति के रुप में विकसित होने की संभावनाओं की तलाश करने और समाज को संरक्षित और सुरक्षित करने का प्रमुख घटक है. राजनैतिक स्वतंत्रता से आशय राज्य प्रशासन में सक्रिय सहभागिता से है और सामाजिक स्वतंत्रता से आशय बोलने और अभिव्यक्ति की

आजादी और अन्य संबंधित मानव अधिकारों से है. ये संकेतक मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं. यदि स्वतंत्रता संकेतकों पर विचार किया जाए ,भारत मानव विकास के संदर्भ में बेहतर स्थिति में है क्योंकि लोग लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं.

4. विकासात्मक कार्यनीतियां – एक तुलनात्मक विश्लेषण

भारत और पाकिस्तान को आई एमएफ और विश्व बैंक के अत्यधिक दबाव के कारण आर्थिक सुधारों को लागू करना पड़ा. इसलिए इन दोनों देशों ने समान परिस्थितियों में अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विश्व बाजारों के लिए खोला. हालांकि विश्व बाजारों से प्रतियोगिता के कारण, इनकी प्रारम्भिक अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ा, इसके परिणामस्वरूप कारण प्रतियोगिता में बने रहने और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए,घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता में बाद में सुधार किया गया.

दूसरी तरफ चीन की एक अलग कहानी है. विदेशी तकनीक का बहिष्कार, विकेन्द्रीकरण और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का माओ का दृष्टिकोण अब जारी रखने योग्य नहीं रहा. इसलिए, चीनी नेताओं ने वैश्विक मानकों के समकक्ष पहुंचने के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास के उच्च स्तर को पाने के लिए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की.

पाकिस्तान में 1990 के दशक में सुधार प्रकिया ने सभी आर्थिक संकेतकों को बिगाड़ दिया. तथापि 1960 के दशक में ग़रीबों का अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक था जो 1980 के दशक में घटकर 25 प्रतिशत हो गया और 1990 के दशक में फिर बढ़ने लगा. पाकिस्तान में विकास की धीमी गति और गरीबी के पुन: उभरने का कारण यह था कि कृषि की वृद्धि और खाद्य आपूर्ति तकनीकी परिवर्तन की संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित न होकर उत्तम फसल पर आधारित थे. जब फसल अच्छी थी तो अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में थी और जब फसल इतनी अच्छी नहीं थी तो आर्थिक संकेतकों ने नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई. पाकिस्तान ने अपने भुगतान संतुलन के संकट को ठीक करने के लिए विश्व बैंक और आई एम एफ से ऋण लिया. किसी भी देश के लिए विदेशी विनिमय एक अनिवार्य घटक है, यदि वह देश निर्मित वस्तुओं के निरंतर निर्यात के द्वारा अपने विदेशी विनिमय अर्जन को बनाने में सक्षम है. पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी विनिमय अर्जन मध्यपूर्व में पाकिस्तानी कामगारों के धन भेजने और कृषि उत्पादों के निर्यात से हुआ. एक तरफ ऋणों पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी और दूसरी तरफ ऋणों का वापस भुगतान करने में बढ़ती हुई कठिनाइयां थीं. फिर भी, पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक वृद्धि को फिर से हासिल कर लिया है और वह इसे बनाए रखने में समर्थ है. 2015-16 में, 2016-17 की वार्षिक योजना में यह कहा गया है कि जीडीपी में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई , जो पिछले आठ वर्षों में सबसे ज्यादा है. जबकि कृषि वृद्धि दर बहुत ज्यादा संतोषप्रद नहीं थी, औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों में क्रमश: 6.8 और 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कई वृहत अर्थ शास्त्र संबंधी संकेतक भी स्थायी और सकारात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाने लगे.

5. सारांश

भारत, चीन और पाकिस्तान ने भिन्न परिणामों के साथ विकास की राह पर लगभग तीन दशकों तक यात्रा की. 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में इन सभी देशों ने कम विकास के एक समान स्तर को बनाए रखा. पिछले तीन दशक इन देशों को विकास के अलग - अलग स्तरों पर ले गये. भारत ने लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखते हुए, मध्यम श्रेणी का निष्पादन किया. अभी भी बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और बुनियादी संरचनात्मक सुविधाएँ अपर्याप्त हैं. इसकी एक चौथाई से अधिक की आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है. पाकिस्तान ने प्रारम्भिक वर्षों में सुस्त रफ्तार का सामना किया लेकिन बाद में वृद्धि की सकारात्मक और अधिक दरें दर्शाना शुरु किया जो आर्थिक पुन: प्रगति को दर्शाता है. चीन में, राजनैतिक

स्वतंत्रता की कमी और मानव अधिकारों के लिए इसके निहितार्थ मुख्य सरोकार हैं. तथापि इसने गरीबी उन्मूलन के साथ – साथ आर्थिक वृद्धि के स्तर को उठाने में सफल हुआ है .चीन ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण करने की अपेक्षा अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए बाजार तंत्र का उपयोग किया हे. भूमि का सामूहिक स्वामित्व बरकरार रखने और व्यक्तियों को भूमि पर खेती करने की अनुमति दे कर, चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है . चीन में सामाजिक बुनियादी संरचनाएं प्रदान करने में सार्वजनिक हस्तेक्षप से मानव विकास संकेतकों में सकारात्मक परिणाम सामने आए है.